

संपादकीय



काश ! पहले ही वार्ता हो जाती -----

कल 20 जुलाई को दिल्ली में जो कुछ हुआ वह नहीं होना चाहिए था। छात्र अपनी मांगों को लेकर लगभग तीन सप्ताह से प्रोटेस्ट कर रहे थे और कल जब उनसे बातचीत करने सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया और सोनम बाइचुंग पुलिस ने जबरन उठकर अस्पताल में भरी कराती तो छात्र आक्रोशित हो गए। फिर छात्रों ने संवेद कूच का निर्णय लिया तो दिल्ली पुलिस ने घेराबंदी कर दी, छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़ना, लाठी चार्ज करना वहां से निकले वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर सरकार ने बातचीत के लिए जेपी नड्डा को नियुक्त तो सीजेपी के दो लोग जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे और उन्होंने अपनी मांग रखी। क्या सरकार पहले ऐसा नहीं कर सकती थी, क्या इस तरह के क्रदम उठाना बर्बरता नहीं थी? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हर नागरिक और हर संगठन को अपनी बात शान्तिपूर्ण तरीके से रखने का अधिकार है। जब किसी मुद्दे पर सरकार और जनता के बीच संवाद कमजोर पड़ जाता है, तब विरोध-प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा बन जाते हैं। हाल ही में सीजेपी द्वारा किए गए विरोध-प्रदर्शन ने भी यही सवाल खड़ा किया है कि यदि सरकार और आंदोलनकारी पहले ही गंभीरता से बातचीत कर लेते, तो क्या प्रश्न इतनी आगे बढ़ती? क्या धरना-प्रदर्शन, तनाव और टकराव से बचा जा सकता था। यदि प्रत्येक किसी एक संगठन या सरकार तक सीमित नहीं है। यह भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की उस चुनौती की ओर संकेत करता है, जहां संवाद की कमी अक्सर आंदोलनों को जन्म देती है। यदि समय रहते बातचीत हो जाए, तो कई विवाद बिना किसी टकराव के सुलझाए जा सकते हैं। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन कोई असामान्य घटना नहीं है। जब लोगों को लगता है कि उनकी समस्याओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है, तब वे सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। संविधान की नागरिकों को शान्तिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है। लेकिन विरोध का उद्देश्य केवल सरकार की आलोचना करना नहीं होना चाहिए। उसका मकसद समाधान तक पहुंचना होना चाहिए। यदि प्रदर्शन केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का माध्यम बन जाए, तो उसका मूल उद्देश्य कमजोर पड़ जाता है। कई बार सरकारें यह मान लेती हैं कि आंदोलन समाज के साथ स्वतः समाप्त हो जाएगा। दूसरी ओर आंदोलनकारी यह मानते हैं कि बिना दबाव बनाए सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी। इसी सोच के कारण दोनों पक्ष अपनी-अपनी स्थिति पर अड़े रहते हैं। यदि शुरुआत में ही दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर बैठ जाएं, तो कई समस्याओं का समाधान निकल सकता है। संवाद केवल समझौता नहीं होता, बल्कि एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का अवसर भी देता है। यदि आंदोलन शुरू होने से पहले या शुरुआती चरण में ही संबंधित पक्षों के बीच औपचारिक वार्ता होती, तो संभव है कि विरोध इतना लंबा न चलता। कई बार केवल आश्वासन नहीं, बल्कि स्पष्ट समस्याओं और एलिखित कार्योंवाजा भी लोगों का विश्वास बढ़ाती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह जनता की चिंताओं को सुने। वहीं आंदोलनकारी संगठनों की भी जिम्मेदारी होती है कि वे बातचीत के सभी लोकतांत्रिक विकल्पों का पूरा उपयोग करें। किसी भी लोकतंत्र में केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं होती। रखें और करने वाले संगठनों की भी जिम्मेदारी होती है कि वे शान्तिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों, अर्थों और बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहें। सरकार को चाहिए कि वह विरोध को केवल राजनीतिक जरूरत से न देखे। यदि किसी मुद्दे पर बड़ी संख्या में लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो उसे गंभीरता से सुनना लोकतांत्रिक दायित्व है। हर बड़ा आंदोलन राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाता है। विपक्ष सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाता है, जबकि सरकार कई बार आंदोलन के पीछे राजनीतिक उद्देश्य होने की बात कहती है। इस माहौल में वास्तविक मुद्दा पीछे छूट जाता है। यदि प्रारंभिक स्तर पर ही संवाद स्थापित हो जाए, तो राजनीतिक टकराव भी कम हो सकता है और जनता का ध्यान समाधान पर केंद्रित रह सकता है। आम नागरिक किसी भी विवाद का शान्तिपूर्ण समाधान चाहता है। लंबा आंदोलन, प्रशासनिक तनाव और राजनीतिक बयानबाजी अंततः जनता को ही प्रभावित करती है। लोग चाहते हैं कि सरकार उनकी बात सुने और संगठन भी समाधान की दिशा में सकरात्मक भूमिका निभाएं। सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि संवाद का कोई विकल्प नहीं है। लोकतंत्र में विरोध और वार्ता दोनों साथ-साथ चलते हैं। यदि केवल विरोध हो और वार्ता न हो, तो समाधान कठिन हो जाता है। यदि केवल आश्वासन हो और कार्रवाई न हो, तो जनता का विश्वास कम होता है। इसलिए आवश्यक है कि भविष्य में किसी भी विवाद को शुरुआती स्तर पर ही बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाए। इससे समय, संसाधन और सामाजिक तनाव—तीनों की बचत होगी। 'काश पहले ही वार्ता कर ली होती' केवल एक भावनात्मक टिप्पणी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। किसी भी आंदोलन का सबसे अच्छा अंत तब होता है, जब दोनों पक्ष समानापूर्वक बातचीत करें और ऐसा समाधान निकालें जो कानून, संविधान और जनहित—तीनों के अनुरूप हो। सरकार और आंदोलनों के बीच विश्वास का पुल केवल संवाद से बनता है। यदि यह संवाद स्तर पर शुरू हो जाए, तो न केवल विरोध-प्रदर्शन की तीव्रता कम हो सकती है, बल्कि लोकतंत्र भी अधिक मजबूत और उत्तरदायी बन सकता है।

राजीव शक्ला (संपादक)

राजीव शुक्ला - (संपादक)



मेघ राशि -मेघ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। अधिकारियों का विश्वास जीतने में सफलता मिलेगी और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। यदि किसी साझेदारी वाले कार्य की योजना बना रहे हैं तो उसमें अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी।

वृषभ राशि—वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। नौकरी करने वालों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जबकि व्यापार से जुड़े लोगों के रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं।

मिथुन राशि-मिथुन राशि के जातकों के लिए आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। शिक्षा, साहित्य, कला अथवा जनसंचार से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

कर्क राशि—कर्क राशि के लोगों के लिए आज परिवार और घरेलू मामलों पर विशेष ध्यान देने का दिन रहेगा। संपत्ति, भवन अथवा वाहन से जुड़ी कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों के कार्यों में विश्वास बनी रहेगी।

सिंह राशि-सिंह राशि के जातकों का आत्मविश्वास आज बढ़ा हुआ रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों को महत्व मिलेगा और अधिकारी भी आपके कार्य से संतुष्ट दिखाई देंगे।

कन्या राशि-कन्या राशि के लोग का आज आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का उचित परिणाम मिलने के संकेत हैं और नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं।
तुला राशि-तुला राशि के जातकों के लिए

आज का दिन विशेष रूप से अनुकूल रहने वाला है। चंद्रमा के आपकी राशि में प्रवेश करने से आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा।

वृश्चिक राशि-वृश्चिक राशि के लोगों को आज धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना होगा। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना आपके हित में रहेगा। लंबे समय से अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने का प्रयास सफल हो सकता है।

धनु राशि- धनु राशि के जातकों के लिए आज मित्रों और सामाजिक संबंधों से लाभ मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और व्यापार में

भी विस्तार के संकेत हैं। लंबे समय से रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होने से मन पसन्न रहेगा।

मकर राशि-मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन करियर की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। प्रयत्नति

नई जिम्मेदारी अथवा अधिकारियों की सराहना मिलने की संभावना है। व्यापार में विस्तार की योजनाएं गति पकड़ सकती हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आय के नए साधन भी सामने आने हैं।

कुंभ राशि-कुंभ राशि के जातकों के लिए आज भाग्य का अच्छा साथ मिलने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं और लंबे समय से

मीन राशि-मीन राशि के लोगों को आज किसी भी कार्य में जल्दबाजी से बचना चाहिए। कार्यक्षेत्र में धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।

प्रदेश के विकास की मजबूत नींव में बेहतर सड़कें और पुल दे रहे हैं गति

किसी भी राज्य या राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक प्रगति उसकी सड़क एवं परिवहन व्यवस्था पर निर्भर करती है। सड़कों केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि वे विकास, निवेश, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि की आधारशिला होती हैं। जब किसी प्रदेश की सड़कों बेहतर होती हैं, तो किसान अपनी उपज समय पर मंडियों तक पहुँचा पाते हैं, उद्योगों को कच्चा माल और तैयार उत्पाद के परिवहन में सुविधा मिलती है, विद्यार्थियों को शिक्षा संस्थानों तक पहुँच आसान होती है तथा मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा एवं उपचार हो पाता है। तब प्रदेश जैसे विशाल क्षेत्र में सर्वाधिक आबादी वाले राज्य में मजबूत सड़क नेटवर्क का महत्व और भी बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने आधारभूत संरचना के विकास को नई दिशा और नई गति प्रदान की है। वर्ष 2012 से 2017 तथा वर्ष 2017 के बाद की अवधि के तुलनात्मक अंकड़े इस परिवर्तन की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। ये अंकड़े केवल निर्माण कार्यों की संख्या नहीं दर्शाते बल्कि बदलती कार्यसंस्कृति, बेहतर योजना, प्रभावी निगरानी और परिणामोन्मुखी प्रशासन का भी प्रमाण हैं। प्रदेश सरकार ने सड़कों के निर्माण एवं चौड़ीकरण को विकास की प्राथमिकता बनाया। इसी सोच का परिणाम है कि जहाँ 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के बीच पाँच वर्षों में कुल 31,868 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवनिर्माण किया गया था, वहीं 01 अप्रैल 2017 के बाद यह उपलब्धि बढ़कर 66,838 किलोमीटर तक पहुँच गई। वर्तमान सरकार

के कार्यकाल में प्रदेश में सड़क निर्माण कार्यों को नई गति और व्यापक विस्तार मिला है। वर्तमान समय में विभाग औसत 20 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से सड़कों का नवीनीकरण और चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य कर रहा है। ये केवल गति को संकेत नहीं, बल्कि बेहतर परियोजना प्रबंधन, समयबद्ध क्रियान्वयन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग का परिचायक है। इस व्यापक सड़क विकास का सबसे बड़ा लाभ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को मिला है। जिन गाँवों तक पहले पहुँचने में घंटों लग जाते थे, वहाँ अब बेहतर सड़क संपर्क के कारण आवागमन सुगम हुआ है। इससे ग्रामीणों के परिवहन की लागत कम हुई है। ग्रामीण बाजारों का विस्तार हुआ है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिल रही है। साथ ही धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों तक बेहतर पहुँच बनने से पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है, जिससे ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। सड़क निर्माण के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। किसी भी सड़क-निर्माण जितना महत्वपूर्ण होता है, उसका समय-समय पर नवीनीकरण और रखरखाव उतना ही आवश्यक होता है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2012-2017 के दौरान 35,843 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया गया था जबकि वर्ष 2017 के बाद यह आँकड़ा बढ़कर 2,93,082 किलोमीटर तक पहुँचा गया। वह लगभग 650 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। वार्षिक औसत में भी उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले जहाँ प्रतिवर्ष औसत 7,168

किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाता था, वहीं अब यह बढ़कर लगभग 3,413 किलोमीटर प्रतिवर्ष हो गया। प्रदेश सरकार द्वारा बनाये जा रहे सड़क रखरखाव की गति पहले की तुलना में चार गुना से अधिक हो चुकी है। बेहतर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ-साथ वाहन की ईंधन खपत घटाने, यात्रा समय कम करने तथा परिवहन लागत में भी लानें में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

इन सड़कों का सीधा प्रभाव स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन पर भी दिखाई देता है। अ एम्बुलेंस सेवाएँ, पुलिस, अग्निशमन पर और अन्य आपदाकालीन सेवाएँ पहले से आँखा कहीं अधिक तेजी से दूरस्थ तक पहुँच पा रही हैं। इससे न केवल लोगों की सुरक्षा बढ़ी है बल्कि अनेक परिस्थितियों में समय पर सहायता मिलने जीवन भी बचाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बढ़ी संख्या में नदियाँ, नाले और जलघात हैं, जो अनेक स्थानों पर आवागमन में बाध बनती रही हैं। ऐसे में पुलों का निर्माण केवल परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक एकीकरण का माध्यम भी है। पुल बनने से दो क्षेत्रों बीच की दूरी कम होती है, व्यापारिक गतिविधियाँ तेज होती हैं और लोगों का समय तथा संसाधन दोनों बचते हैं। वर्ष 2012 से 2017 के बीच प्रदेश में 591 पुलों का निर्माण किया गया था। वर्षों 2010 के बाद दीर्घ, लघु एवं उपरिगामी निर्माण पुलों की संख्या लगभग दो हजार हो गई। पुल निर्माण में लगभग तीन गुना वृद्धि देखी गई। वार्षिक औसत भी 118 पुल प्रति वर्ष से बढ़कर लगभग 211 पुल प्रति वर्ष हो गया। इससे अनेक ऐसे क्षेत्र, जो पहले बरसात के मौसम में कट जाते थे, अब

उर प्रदेश जैसे विशाल और सर्वाधिक आबादी वाले राज्य में मजबूत सड़क नेटवर्क का महत्व और भी बढ़ जाता है। म्युमंत्रि श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने आधारभूत संरचना के विकास को नई दिशा और नई गति प्रदान की है। वर्ष 2012 से 2017 तथा वर्ष 2017 के बाद की अवधि के तुलनात्मक आँकड़े इस परिवर्तन की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। ये आँकड़े केवल निर्माण कार्यों की संख्या नहीं दर्शाते, बल्कि बदलती कार्यसंस्कृति, बेहतर योजना, प्रभावी निगरानी और परिणामोन्मुखी प्रशासन का भी प्रमाण हैं। प्रदेश सरकार ने सड़कों के निर्माण एवं चौड़ीकरण को विकास की प्राथमिकता बनाया। इसी सोच का परिणाम है कि जहाँ 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के बीच पाँच वर्षों में कुल 31,868 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवनिर्माण किया गया था, वहीं 01 अप्रैल 2017 के बाद यह उपलब्धि बढ़कर 66,838 किलोमीटर तक पहुँच गई। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में सड़क निर्माण कार्यों को नई गति और व्यापक विस्तार मिला है।

वर्ष निर्बाध रूप से जुड़े रहते हैं। बेसड़क और पुल नेटवर्क का सकारात्मक प्रभाव प्रदेश की औद्योगिक वस्त्र पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। परिवहन की कमी हमने से उद्योगों और व्यापार को मिली है। कृषि उत्पाद तेजी से बाजार पहुँच रहे हैं, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावनाएँ बढ़ी निवेशकों के लिए मजबूत आधार संरचना हमेशा आकर्षण का केंद्र होती इसलिए बेहतर कनेक्टिविटी औद्योगिक निवेश और नए रोजगार सृजन के लिए भी अनुकूल वातावरण तैयार रही है। आज उत्तर प्रदेश का सड़क एवं नेटवर्क केवल भौतिक संरचना का विकास नहीं है, बल्कि यह देश के समग्र विकास का आधार बन चुका है। कनेक्टिविटी से शिक्षा, स्वास्थ्य, क

उद्योग, पर्यटन और निवेश जैसे सभी क्षेत्रों को नई गति मिली है। यह परिवर्तन केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रवेश के कोड़ों नागरिकों के दैनिक जीवन में महसूस किया जा सकता है। प्रदेश सरकार की स्पष्ट नीति, मजबूत नेतृत्व, प्रभावी कार्ययोजना और जवाबदेह कार्यसंस्कृति के समन्वय से निर्माण कार्य हो रहे हैं। वर्ष 2017 के बाद सड़क एवं पुल निर्माण की जिस गति और व्यापकता के साथ कार्य हुए हैं, ये निर्माण उक्त प्रदेश के आधुनिक आधारभूत संरचना वाले राज्यों की श्रेणी में मजबूती से स्थापित किया है। आने वाले वर्षों में यही मजबूत बुनियादी ढांचा प्रदेश की आर्थिक प्रगति, निवेश वृद्धि और समावेशी विकास की सबसे बड़ी ताकत बनेगा।

-અભિષેક સિંહ

संतुलित आहार पर अनुदान निरंतर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही, जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित नियमित प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से मत्स्य पालकों को जल की गुणवत्ता, वैज्ञानिक रख-रखाव, बीमारी नियंत्रण और आहार प्रबंधन से संबंधित बारीकियों का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, ताकि जीविक कमान्यूनतम करके उत्पादकता और लाभ को अधिकृत किया जा सके। उत्पादित मछलियों के उचित मूल्य प्रबंधन, गुणवत्ता संरक्षण और त्वरित विपणन के लिए प्रदेश भर में कोल्ड चेन, रेफ्रिजरेटेड वाहनों और आधुनिक मत्स्य बाजारों का मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। इससे मेकैनिट प्रयासों से बचौलियों की भूमिका समाप्त हो रही है और उत्पादकों को उनका उपज का सीधा और वाजिब मूल्य मिल पा रहा है। विपणन व्यवस्था के सुदृढ़ होने से ग्रामीण क्षेत्रों में एक नए व्यापारिक और व्यावसायिक तंत्र का निरंतर विकास हो रहा है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के एकीकृत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में मजबूती से स्थापित हो चुका है। प्रतापगढ़ जनपद के रणजय सिंह जैसे प्रतिनिधित्व मत्स्य पालकों की सक्रियता यह सिद्ध करती है कि सही मार्गदर्शन के साथ सरकारी योजनाओं से जुड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े स्तर पर आर्थिक परिवर्तन लाया जा सकता है। ऐसे प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में पलायन को रोकने में भी कारगर हो रहे हैं।

जनपद- प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ में बायोप्लॉक तकनीक से नीली क्रांति को मिली रफ्तार, रणंजय सिंह बने स्वरोजगार की मिसाल

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और ग्रामीण युवाओं को निरवरोधता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन को एक अग्रणी स्तंभ के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी नीतियों, आधुनिक तकनीकों के समावेश और जनकल्याणाकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य का मत्स्य उत्पादन नौली क्रांति को नई ऊँचाइयों को छू रहा है। राज्य सरकार द्वारा मत्स्य विकास को विशेष प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एवं 'मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना' का धरातल पर सफल संचालन किया जा रहा है। इन दूरगामी योजनाओं के माध्यम से न केवल राज्य में अच्छी उत्पादन में अभूतपूर्व और रिकार्ड ब्रिचिंग दर्ज की गई है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति आज की गैर है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक औद्योगिक और स्वरोजगार के निर्माण साधन भी निरंतर सृजित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का मुख्य लक्ष्य गांवों से होने वाले पलायन को समस्यावरण प्रभावित करने वाली लगाया तथा ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार देने वाला बनाना है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में चलाए जा रहे अभियानों का कार्यक्रम प्रति-ग्रामीण युवाओं को स्वावलंबन और आत्मनिष्ठा का नया आयाम दिखाया है। इसी क्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चलाए जा रहे व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों, पारदर्शी प्रक्रियाओं तथा ऑनलाइन आवेदन प्रणालियों से एक सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित की गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से जलसम्पद, पात्र और

इच्छुक युवाओं तक योजनाओं का सीधा
 और पारदर्शी लाभ पहुँच रहा है। इसी क्रम में
 जनपद प्रतापगढ़ के विकास खंड सण्डव
 चन्द्रिका स्थित ग्राम कटका मानापुर पर
 निवासी रणजय सिंह ने मत्स्य पालन के क्षेत्र
 में उल्लेखनीय सफलता अर्जित कर क्षेत्र के
 अन्य युवाओं तथा किसानों के सामने एक
 उत्कृष्ट उदाहरण और प्रेरणा प्रस्तुत की है।
 पूर्व में पारंपरिक खेती-किसानी पर निर्भर
 रहने के कारण सीमित कृषि भूमि और
 निरंतर बढ़ती कृषि लागत के चलते उन्हें
 अपेक्षित आर्थिक लाभ नहीं मिला पा रहा
 था। पारंपरिक खेती से परिवार का भरण-
 पोषण तो हो जाता था, लेकिन आर्थिक
 प्रगति की गति अत्यंत धीमी थी। ऐसे समय
 में समाचार पत्रों, विभागीय प्रचार माध्यमों
 तथा विज्ञप्ति के जरिए उन्हें मत्स्य पालन
 और विशेष रूप से बायोफ्लोक तकनीक की
 विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। जिला प्रशासन
 एवं संबंधित विभागीय योजनाओं के
 तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से प्रेरित
 होकर उन्होंने आधुनिक मत्स्य पालन को
 अपनाते का निश्चय किया। इसके उपरान्त
 उन्होंने एक लाखगाभा 0.10 हेक्टेयर जमीन
 भूमि पर आधुनिक बायोफ्लोक प्रणाली के
 तहत मत्स्य पालन इकाई की स्थापना कर
 प्रारंभ प्रारंभ किया। इस इकाई में पंगेशियस
 काय की मछलियों के पालन हेतु
 विभागीय स्वीकृति मिलने के उपरान्त उन्होंने
 निजी बोरिंग, विद्युत संयोजन और सुरक्षित
 भंडारण जैसी आवश्यक बुनियादी
 सुविधाओं का विकास किया। काम पार
 और सीमित भूमि में अधिक उत्पादन देने
 वाली यह पर्यावरण-अनुकूल प्रणाली उनके

लिए अत्यंत लाभदायक और प्रभावकारी साबित हुई। चरणबद्ध तरीके से मत्स्य बीज का संरक्षण, वैज्ञानिक जल प्रबंधन और आहार निर्वहन अपनाते हुए उनकी इकाई इकाई से औसतन 1.40 टन प्रति वर्ष मछली का उत्पादन प्राप्त होने लगा। आर्थिक दृष्टि से भी यह फल अत्यंत सफल और प्रेरणादायक सिद्ध हुई है। वर्तमान में उनका इकाई प्रति लगभग 7 लाख रुपये की वार्षिक लागत आती है, जबकि उत्पादित मछली की बिक्री से प्रतिवर्ष लगभग 18 लाख रुपये तक की सकल आय अर्जित हो रही है। इस आवश्यक संचालन व्ययों को घटाने पश्चात उन्हें प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख रुपये की शुद्ध आय प्राप्त हो रही है, जो पारंपरिक मत्स्य खेती की तुलना में कई गुना अधिक है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लगभग 10 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार की उपलब्धि हुआ है, जिससे ग्रामीण युवाओं को गांव में ही आजीविका मिल रही है। उत्तर प्रदेश में पारंपरिक मत्स्य पालन से आगे बढ़ते हुए अब बायोफ्लोरा प्रणाली, रीसकुल्टिंग एक्वाकल्चर सिस्टम (आएएसएस) और केज कल्चर जैसे आधुनिक तकनीकों को व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये आधुनिक प्रणालियाँ कम लागत, सीमित जल और न्यूनतम भूमि में भी अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करती हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित, प्रगतिशील और तकनीकी युवा इस व्यवसाय की ओर तेजी आकर्षित हो रहे हैं और कृषि आधारित सहायक उद्यमों को एक नई दिशा दे रहे हैं।

इन बहुप्राणी योजनाओं के माध्यम से न केवल राज्य में मछली उत्पादन में अभूतपूर्व और बड़े पैमाने पर वृद्धि दृष्टि की गई है, बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में स्थायी आजीविका और स्वरोजगार के नये-नये साधन भी संवर्धित हुए रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का मु्य प्रयेय ग्रामीण होना वाले पारम्परिक की समस्या पर प्रभावी और तगना तथा राजीग युवाओं को आमूलभूमि बनाकर रोजगार देने वाला बनाना है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में चला जा रहे अभियानों और कार्यक्रमों ने ग्रामीण युवाओं को स्वयम्भूत और आमूलभर्नता के नया मार्ग दिखाया है। इसी कम में प्रदेश विभिन्न जनपदों में चलाए जा रहे व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों, पारदर्शी प्रक्रियाओं और ऑनलाइन आवेदन प्रणालियों से एक सुव्यवस्था स्थापित की गई है।

समरसता को विशेष गति देने के उद्देश्य
स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के
मत्स्य पालन गतिविधियों, जैसे मत्स्य
उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन स
पैमाने पर जोड़ा जा रहा है। इस पहल
ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक
आर्थिक सशक्तिकरण में अत्यंत महत्व
भूमिका निभाई है। इसके साथ ही,
सभाओं के तालाबों को पट्टे पर देने
पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से स्था
मधुआरा समुदायों, पारंपरिक मत्स्य पाल
और भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता
जा रही है, जिससे उनकी आय में नि
और स्थायी वृद्धि हो रही है। मत्स्य पाल
को आर्थिक सुरक्षा एवं जोखिम प्र
प्रदान करने के उद्देश्य से बीमा कव
निसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की युति
उच्च गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज

समाप्त हो रही है और उत्पादकों को उनकी उच्च कीमतों का सीधा और वाजिब मूल्य मिल पा रहा है। विपणन व्यवस्था के सुदृढ़ होने से ग्रामीण क्षेत्रों में एक नए व्यापारिक और व्यावसायिक तंत्र का निरंतर विकास हो रहा है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के एकीकृत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज अंतर्राष्ट्रीय मूल्य उत्पादन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में मजबूती से स्थापित हो चुका है। प्रतापगढ़ जनपद के रणजय सिंह जैसे प्रतिभाशाली मूल्य पालकों की सकलतः यह सिद्ध करती है कि सही मार्गदर्शन के साथ सरकारी योजनाओं से जुड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े स्तर पर आर्थिक परिवर्तन लाया जा सकता है। ऐसे प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में पलायन को रोकने में भी कारगर हो रहे हैं।

रिमझिम में लुत्फ देगा घर का 'रेन कैफे'

बारिश के दिनों में जब बाहर रिमझिम
 बूँदों की छड़ी लगी हो, उन दिनों घर के
 पीतर एक ऐसा कोना बनाएँ, जो सुकून दे,
 चनात्मकता का अहसास कराए और घर र
 नजर न निकल पारे पर परेशान न करे
 मल्लिक उल्टे खूबसूरत पलों का अहसास दे।
 जगह, बारिश की पहली फुहार पड़ते ही सब
 कुछ धीमा हो जाता है। खिचकी पर गिरती
 हैं, कच्ची मिट्टी की सौंधी खुशबू की उमंग
 और कई जुगुन हो जाती हैं, जब हाथ में
 लौकी का मग हो और कोई पसंदीदा
 कताब। जी हाँ, यह दृश्य किसी रेन कैफे
 का ही लगता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि रेन
 कैफे घर के बाहर ही ढूँढ़ जाएँ। थोड़ी सी
 चनात्मकता से घर के अंदर भी एक कोने
 को रेन कैफे में बदला जा सकता है और इन
 दिनों रेन कैफे एट होम का एक ट्रेंड भी चल
 रहा है। आज लोग केवल सुंदर घर नहीं
 बल्कि एक ऐसा आशियाना चाहते हैं, जो



उन्हें रचनात्मक लाफेस्टाइल दें। लंबे समय तक स्क्रीन से जुड़े रहने, लगातार काम करने और सोशल मीडिया की व्यस्तता के बीच लोग ऐसे निजी स्थान तलाश रहे हैं, जहाँ कुछ समय वह स्वयं के सांख्यिक रचनात्मक माहौल में गुजार सकें। घर के अंदर रचनात्मक इसी का एक विकल्प है। जहाँ लिखा-पढ़ा भी जा सके, मनपसंद संगीत सुना जा सके और जब मन करे परिवार के लोगों से बातें

करना और खिड़की से बाहर बारिश निहारना भी एक सुखद अनुभव बन जाए। सबसे पहले इसे अपने मन में सही जाह चुनें। जहां प्राकृतिक रोशनी आती हो और यदि संभव हो तो घर के बाहर का भी दृश्य दिखायी देता हो। खिड़की के पास रखी आरामदायक कुर्सी, फर्श पर पड़ा गद्दा यह विकल्प हो सकता है। यदि बालकनी, बेडरूम का कोना कोई शांत हिस्सा भी इसके दरअसल इस कोने के लिए याथार्थिका आम्राम होनी कुशन, हल्का कंबल, सूती कुर्सी और आरामदायक बैठने न कैफे एट होम का यही

है। वर के अंदर रखे छोटे-
एक कोने में झुरमुट भी एक
कल्पनाशीलता का अहसास
भी फ्टांट, पीसा लिली, स्नेक
किस्म के इंडोरो पोथे, अगर
कट्टे रखें हों तो उनको झुरमुट
एक खास तरह की ताजगी से
दि बालकनी ऐसी हो जहां
उत्कर कॉफी और चाय का
दुनिया के नजारे देखे जा
सकें तो कहना ही क्या? इस
गुलसी, पुदीना या लेमन ग्रास
ध भी देते हैं। मन और नजरों
वाली से भी जोड़ते हैं। लेकिन
य रेशना का होना खास है।
श के मौसम में प्राकृतिक
तह से सेरोताजा करती है। रेन
दिमाग में सुकृद्वानक दृश्य
हैं, जब हल्का सा संगीत बज
रहा हो और
रेन कैफे
में पहुंचा
वातावरण
कविता स
तरह के अ
मतलब के
में अंदरूख
वाली ग्रीन
चॉकलेट
मानसुख
ग्रामना, इ
बने हल्के
दोनों का र
का मजा
जाता है, ज
को खुद
बातचीत
व्यस्त रहे

हाथ में किताब हो। तब तो मानो
 आपको एक इंग्लैलेक्चुअल बैक
 ता है। ऐसे मौसम में और ऐसे
 उपन्यास, कोई यात्रा वृत्तान्त,
 हा या डायरी पढ़ना एक खास
 से भर देता है। रेन कैफे का
 ल मसाला चाय नहीं है। वास्तव
 तुलसी की चाय, दालचीनी
 गी, लेमन ग्रास, हर्बल टी, हॉट
 घर में बने हल्के सूप भी
 आनंद बढ़ाते हैं। साथ में भुना
 ई फ्रूट्स, कॉर्न चाट या घर के
 नक्स रखें ताकि स्वाद और सेहत
 तुलन बना रहे। रेन कैफे एट होम
 महत्व तब और अधिक बढ़
 त हम यहां बैठते समय मोबाइल
 दूर रखें। परिवार के साथ
 न, बच्चों के साथ बोर्ड गेम में

